MATI MARGARET ALVA): (a) A meeting of the Secretaries/Special Secretaries/Additional Secretaries and Joint Secretaries was addressed by the Prime Minister on 30th January, 1993.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The normal official channel which exists already takes care of such intentions.

Empanelment for the post of Additional Secretary

3057. SHRI DINESH BHAI TRIVEDI:
MISS SAROJ KHAPARDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Civil Services Board headed by Cabinet Secretary has recommended 18 Additional Secretaries for empanelment to post of Secretaries;

(b) if so, when was the recommendation made; and

(c) whether the board had considered the fact that a large number of these 18 officers have served abroad with international agencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS((SHMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) Selection for inclusion in the panel of officers suitable for appointment to the post of Secretaries and posts equivalent thereto are approved by the Appointments Committee of the Cabinet on the basis of the proposals submitted by the Cabinet Secretary. In this task, the Cabinet Secretary is assisted by a Special Committee of Secretaries. Inclusion in such panels is through the process of evaluation of such qualities as merit, competence, leadership, and flair for participating in the policy making process. The posts of Secretaries are not cadre posts for any Service and as such, are not to be considered as posts for betterment of promotion prospects.

The empanelment for the post of Secretaries/equivalent in an on-going process and the eligible officers of various Central Services Group 'A' and the All India Services are assessed for their suitability for empanelment.

अपर सचिव पद के लिए पैनल का बनाया जाना

3057. **श्री दिनेश भाई त्रिवेदी :**
कुमारी सरोज खापर्डे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंडलीय सचिव की अध्यक्षता वाले सिविल सेवा बोर्ड ने सचिव के पदों के लिए पैनल हेतु 18 अपर सचिवों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब की गई ; और

(ग) क्या बोर्ड ने इस तथ्य पर विचार किया था कि इन 18 अधिकारियों में से अधिकतर अधिकारी विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशनज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) सचिव के पद तथा उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए किए गए चयन का अनुमोदन मंत्रिमंडल सचिव द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। इस कार्य

में सचिवों की विशेष समिति द्वारा मंत्रिमंडल सचिव को मदद की जाती है, ऐसे पैनलों में नाम, योग्यता, सक्षमता नेतृत्व, और नीति निर्धारण प्रक्रिया में सहभागिता के लिए सूक्ष्मदर्शिता जैसी विशेषताओं का मूल्यांकन करके ही शामिल किए जाते हैं। किसी सेवा के लिए सचिवों के पद नहीं होते और इन पदों पर विचार किसी सेवा के पदोन्नति अवसरों को बेहतरी के लिए नहीं किया जाता है।

सचिव/समवक्ष पदों को पैनल में शामिल किया जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के समूह "क" और अखिल भारतीय सेवा के पात्र अधिकारियों को उपयुक्तता का पैनल हेतु मूल्यांकन किया जाता है।

उच्च श्रेणी लिपिक/निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमानों में संशोधन किया जाना

3058. **श्रीमती कैलाशपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार/दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मौजूदा वेतनमानों में संशोधन करने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार इन ज्ञापनों में की गई सिफारिशों को लागू करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Average working hours and holidays in Government offices

3059. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will he PRIME MINISTER be pleased to state what are the average working hours and holidays for Government offices and public sector units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Central Government adminintrative offices observe 42½ hours a week including lunch break. These offices observe 17 holidays in a year. In respect of non-administrative offices, working hours and holidays (subject to a maximum of 17 holidays are fixed based on functional requirements by the respective Departments. In respect of Public Sector Undertakings the working hours are normally spelt out in the wage settlement or other relevant rules of the PSU concerned. The number of holidays is decided by the management of the PSUs.

Extension to Officers during deputation

3060. DR. SANJAYA SINH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of officers above the level of Deputy Secretary who were refused extension of their tenures in 1991 and 1992; and

(b) whether any extension has been granted during deputation to such officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE